www.tamsasanket.com
वर्षः 05 || अंक 301 || लखनऊ
बुधवार
04 फ़रवरी 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 06:43
सूर्यास्तः 05:43
अधिकतमः 23:00
न्यूनतमः 12:00

» पेज 03

विशेष समाचार | मद्रास हाई कोर्ट ने दीपम पर डीएमके... » पेज 02 | यूजीसी के सपोर्ट में छात्रों का हंगामा... » पेज 04 | धुरंधर 2 का पोस्टर जारी...

2027 में होगा बुल और बुलडोज़र का इलाज

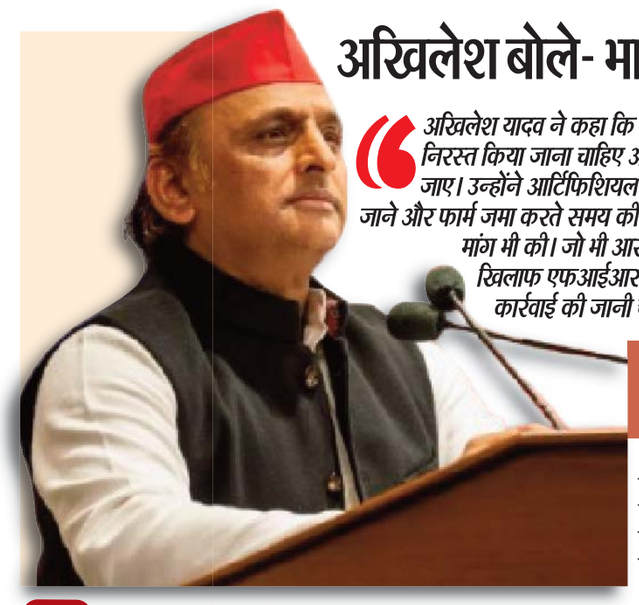

अखिलेश बोले- भाजपा फार्म 7 के जरिए अल्पसंख्यकों का वोट काटने की साजिश रच रही है

“अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक जमा किए गए फार्म 7 को निरस्त किया जाना चाहिए और हस्ताक्षरों की न्यायिक जांच कराई जाए। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के माध्यम से धांधली पकड़े जाने और फार्म जमा करते समय की सीसीटीवी फुटेज निकाले जाने की मांग भी की। जो भी आरोपी पकड़ा जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 420 की धाराओं में कार्रवाई की जानी चाहिए।”

भाजपा पर वोट कटाने की साजिश का आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह हार के डर से घबराई हुई है उन्होंने बताया कि पेन ड्राइव के जरिए लक्ष्य तय कर विधानसभाओं में वोट काटने की सूची तैयार की जा रही है।

कई विधानसभा क्षेत्रों में धांधली की जानकारी

अखिलेश यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि बछरावा विधानसभा क्षेत्र से 32 हजार से अधिक वोट काटने का लक्ष्य बनाया गया है, जबकि अकबरपुर से 8 हजार, गोण्डा की कर्नलगंज में 6,321 और रायबरेली के सरेनी में 3,300 वोट काटने का षडयंत्र तैयार किया गया है। उन्होंने सुल्तानपुर सदर और लखनऊ के सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र समेत कई इलाकों में फर्जी हस्ताक्षर कर फार्म 7 जमा कराने का आरोप लगाया।

आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाया कि भाजपा फार्म 7 के माध्यम से पीडीए और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के वोट काटने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और विधानसभाओं से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बाबत चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें भी दी हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात आईएएस अधिकारी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को फोन कर समाजवादी पार्टी के समर्थकों और पीडीए वोटरों के खिलाफ दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि फार्म 7 के जरिए हो रही धांधली को तुरंत रोका जाए। साथ ही फार्मों के सत्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था, हर फार्म पर नंबरिंग और कागजी फार्म पर निर्वाचन आयोग का होलोग्राम अनिवार्य किया जाए।

2027 चुनाव की अपील

अखिलेश ने इस मौके पर जनता से सपा को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव में लोग बुल (आवारा सांड) और बुलडोजर दोनों से छुटकारा पा लेंगे। यह पोस्ट 2027 चुनाव की तैयारी का हिस्सा लगता है। सपा लगातार योगी सरकार पर हमले कर रही है, जैसे बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर। भाजपा भी जवाब दे रही है, लेकिन यह पोस्ट ने बहस तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे हमले आम हैं। 2022 चुनाव में सपा हारी थी, लेकिन अब अखिलेश मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वीडियो से पता चलता है कि आवारा पशु समस्या गंभीर है।

अखिलेश यादव की चेतावनी

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि ऐसी धांधली रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आयोग निष्क्रिय रहा, तो उसे अपनी बिल्डिंग पर भाजपा का झंडा लगा देना चाहिए। वीडियो में एक छोटी बच्ची पर सांड हमला करता है, लेकिन कुछ बहादुर लोग उसे बचा लेते हैं।

बीएलओ और मुख्य चुनाव अधिकारी पर सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी और बीएलओ किस पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बीएलओ का नाम ही वोटर लिस्ट से काटने की सूची में भेज दिया है। लोगों को वोट देखने पर विधानसभा की लिस्ट दिखाने के बजाय पंचायत की सूची दिखाई जा रही है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक सीसीटीवी फुटेज वाला वीडियो शेयर किया। वीडियो में एक आवारा सांड (बुल) सड़क पर हमला करता नजर आ रहा है। संकरी गली में पार्क कारों और लोगों के बीच सांड दौड़ता है, कारों को टक्कर मारता है और लोगों को भगाता है।

फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाना

अखिलेश यादव ने कहा कि जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में 26 फार्म जमा किए गए, जिनमें नंदलाल के नाम से दो फार्म जमा हुए जबकि उन्होंने कभी हस्ताक्षर नहीं किए। इसी तरह सरोजनीनगर में दशरथ कुमार के नाम पर 100 फार्म जमा किए गए, जबकि वे हस्ताक्षर करना नहीं जानते और अंगूठा लगाते हैं।

पूर्व मंत्रियों और विधायकों की शिकायतें

इस अवसर पर पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह और पूर्व विधायक अरुण वर्मा ने अपने क्षेत्रों में हुई धांधली की जानकारी साझा की। योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि पेन ड्राइव के माध्यम से नाम काटने की साजिशें चल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा हार के डर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहे और कोई भी साजिश सफल न हो। कारों को टक्कर मारता है और लोगों को भगाता है। अखिलेश ने कैप्शन में लिखा कि अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोज़र दोनों का इलाज कर देगी।

यूपी में 32,679 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित

जून में तीन दिन होंगे लिखित एग्जाम

ऐलान

तमसा संकेत, एजेंसी

उत्तर प्रदेश। यूपी में 32,679 कांस्टेबल भर्ती- 2025 परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) के अनुसार, परीक्षा जून 2026 में कराई जाएगी। बोर्ड ने इसका आधिकारिक नोटिस मंगलवार शाम जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा 8 जून, 9 जून और 10 जून को आयोजित होगी। परीक्षा हर दिन अलग-अलग 2 शिफ्ट में कराई जाएगी। भर्ती बोर्ड ने कहा- उम्मीदवार एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी निर्देशों के लिए नियमित रूप से uppbpb.gov.in वेबसाइट चेक करते रहें।

» (शेष पेज 04 पर)

30 जनवरी तक चली आवेदन प्रक्रिया

भर्ती बोर्ड ने 32,679 कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए 31 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया था। आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 30 जनवरी 2026 तक चली थी। लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी।

मेटा-वॉट्सएप कानून मानें या भारत छोड़ें : सुप्रीम कोर्ट

भारतीयों का डेटा शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेटा और वॉट्सएप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। आप इस देशवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यदि आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते, तो भारत छोड़ दें। हम नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता नहीं होने देंगे।

कोर्ट ने कहा- प्राइवेसी पॉलिसी चतुराई से तैयार की जाती हैं

कोर्ट ने कहा कि हम आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। आपको इस पर साफ-साफ भरोसा दिलाना होगा, नहीं तो कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। मेटा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और व्हाट्सएप की ओर से अखिल सिब्बल पेश हुए। दोनों ने बताया कि जुर्माने की राशि जमा करा दी गई है।

फास्ट न्यूज

एअर इंडिया ड्रीमलाइनर के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच शुरू

नई दिल्ली। एअर इंडिया ने अपने सभी 787 ड्रीमलाइनर विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की दोबारा जांच कर दी है। यह फैसला लंदन के हीथ्रो से बेंगलुरु विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी के बाद लिया गया है। विमान में 200 यात्री सवार थे। एयर इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष उप्पल ने बोइंग 787 के पायलटों को ईमेल भेजकर यह जानकारी दी।

7 महीने बाद जेल से बाहर आए मजीठिया

अमृतसर/पटियाला। पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल (SAD) के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया 7 महीने बाद मंगलवार (3 फरवरी) को दोपहर 2 बजे पटियाला की नाभा जेल से बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आते ही समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने मूंछों पर ताव दिया। समर्थकों को संबोधित करते हुए मजीठिया ने कहा- जितना सरकार ने दबाया, उतनी ताकत मिली। दिल्ली हुक्मरानों के साथ ईंट से ईंट टकरानी है। मुझे इस बात की प्रेरणा मिली है। जेल में भी मैं भगवंत मान और केजरीवाल के नाम वाले तकिए घुटनों के नीचे रखकर सोता था।

आंगनबाड़ी के बच्चों को मधुमक्खियों से बचाने दे दी जान

नीमच। नीमच में आंगनबाड़ी केंद्र पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। बच्चों को उनसे बचाने के लिए केंद्र में खाना बनाने वाले स्वसहायता समूह की अध्यक्ष कंचन बाई मेघवाल मधुमक्खियों के सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी बच्चों को तिरपाल और दरी में लपेटा। फिर अंदर के कमरे में भेजा। इतनी देर में कंचन बाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

ईसी ने 6 पत्रों का जवाब नहीं दिया : ममता बनर्जी

चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों, घुसपैठियों के लिए केंद्र जिम्मेदार

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को इलेक्शन कमिशन पर सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले SIR क्यों किया जा रहा है? चार राज्य बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव होने है। SIR तीन राज्यों में हो रहा है, लेकिन भाजपा-शासित असम में नहीं। क्योंकि वह 'डबल इंजन' राज्य है। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों पर कहा कि ये लोग (BJP) घुसपैठियों की बात करते हैं लेकिन ये तो आपकी जिम्मेदारी है। बॉर्डर की रखवाली केंद्र की जिम्मेदारी है। ऐसे में घुसपैठ के लिए वही जिम्मेदार है। ममता बनर्जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पीछे कई लोग बैठे दिखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी SIR के पीड़ित हैं।

उन्होंने कहा कि वह चाहतीं तो लाखों लोगों को दिल्ली ला सकती थीं, लेकिन ये लोग पिछले छह-सात दिनों से यहां रुके हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने ही दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है। एक राज्य की मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त को छह पत्र लिखे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया गया।

» (शेष पेज 04 पर)

गोयल बोले- इससे इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मरीन गुड्स सेक्टर को फायदा, दोनों देश जल्द साझा बयान देंगे

अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार का पहला बयान

तमसा संकेत, एजेंसी

अमेरिका से ट्रेड डील पर भारत सरकार का पहला बयान आया है। मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से कहा कि इस डील से किसी के हितों से समझौता नहीं किया गया है। दोनों देश इस डील पर जल्द ही इस पर साझा बयान जारी करेंगे। यह एक ऐसी डील है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों सेक्टर को सपोर्ट किया है, उनके हितों की रक्षा की। जो लोग अलग-अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खासकर ऐसे सेक्टर जिनमें ज्यादा मेहनत लगती है और जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। सभी इससे उत्साहित हैं। गोयल ने कहा कि ये डील करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का धन्यवाद, उन्होंने PM मोदी की मित्रता का सम्मान किया। ट्रम्प ने दावा किया कि

मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। ट्रम्प के मुताबिक, जरूरत पड़ी तो भारत वेनेजुएला से तेल लेगा। भारत 'बाय अमेरिकन' नीति के तहत अमेरिका से 46 लाख करोड़ रुपए (500 अरब डॉलर) से अधिक का सामान खरीदेगा। वहीं, ट्रम्प के एलान के बाद पीएम ने X पर लिखा- भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रम्प का शुक्रिया।

» (शेष पेज 04 पर)

अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया

भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को बिजनेस डील का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था। ट्रम्प ने कहा था कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रम्प ने अप्रैल में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ (जैसे को तैसा) लगाया था और रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% पेनल्टी का ऐलान किया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया था। अब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि भारत पर सिर्फ टैरिफ 18% ही लगेगा। अमेरिका रूसी तेल खरीदने के कारण लगा 25% टैरिफ हटा देगा। ट्रम्प ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ट्रेड डील की घोषणा की।

पीयूष गोयल की 5 बड़ी बातें...

- इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा। इससे हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर्स के पार्ट्स बनाने वाले, टेक्सटाइल, मरीन गुड, ज्वेलर सेक्टर समेत सभी मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर को बहुत सारे मौके मिलेंगे।
- राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता इस डील का विरोध इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक है। इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का धन्यवाद, उन्होंने PM मोदी की मित्रता का सम्मान किया। साथ ही हमारी स्पर्धा वाले देशों में सबसे अच्छा और बढ़िया ट्रेड डील दिया।
- यह ट्रेड डील भारत की इकॉनमी के लिए, भारत के सभी 140 करोड़ नागरिकों के लिए, गांवों में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति, किसान, मछुआरे, नौजवान और महिला, हमारी बहनों और महिलाओं के लिए बहुत सारे मौके लाएगी।
- हमने पूरे देश से रिपोर्ट्स देखी हैं। बड़े पैमाने पर उत्साह है। भारत के एक्सपोर्ट से जुड़े सभी लोग, भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े लोग, जो लोग भारत में मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं और जो लोग अलग-अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।

“राहुल ने कहा- नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने उनकी इमेज बनाई वे अब यह इमेज तोड़ रहे हैं। अमेरिका में अडानी पर केस है, यह असल में मोदी पर केस है। वो मोदी जी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं।”

ताजपोशी : भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए ■ राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी को खत्म हो रहा

युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें सीएम होंगे

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली/इम्फाल। भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। मंगलवार को BJP विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। अब राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। भाजपा सूत्रों के मुताबिक कुकी-जो समुदाय को संतुष्ट करने के लिए 10 कुकी विधायकों में से एक को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद, 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 12 फरवरी 2026 राष्ट्रपति शासन खत्म हो रहा है। युमनाम खेमचंद सिंह पारंपरिक ताइक्वांडो में 5th डैन ब्लैक बेल्ट पाने वाले भारतीय भी हैं। उन्हें इसका प्रमाणपत्र 30 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया की

दिल्ली में भाजपा कार्यालय में युमनाम खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया।

राजधानी सियोल में ग्लोबल ट्रेडिशनल ताइक्वांडो फेडरेशन (GTTF) के ऑफिस में दिया गया था। ताइक्वांडो और अन्य मार्शल आर्ट्स में डैन (Dan) का मतलब होता है ब्लैक बेल्ट के स्तर। ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद आगे की सभी रैंक को डैन कहा जाता है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच मई 2023 में हिंसा की शुरुआत हुई थी। इसमें अब तक करीब

“इस दौरान मणिपुर के विधायक दल का नेता चुनने के लिए नियुक्त सेंट्रल ऑब्जर्वर तरुण चुग, संबित पात्रा और मणिपुर के पूर्व सीएम बीरेन सिंह भी मौजूद रहे। मणिपुर से एनडीए के करीब 20 विधायक रविवार रात को दिल्ली पहुंचे थे। वहीं अन्य विधायक सोमवार को केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राजधानी पहुंचे।”

260 लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य में करीब दो साल तक हिंसा न रोक पाने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था।

» (शेष पेज 04 पर)

लोकसभा में राहुल के भाषण पर लगातार दूसरे दिन हंगामा

नरवणे पर आर्टिकल दिखाया, तो स्पीकर ने रोका

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राहुल ने मंगलवार दोपहर 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया। कहा- मुझे बोलने दिया जाए उनके यह कहते ही एनडीए के सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया। आज वे 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। इस बीच हंगामा तेज होता गया। लेकिन राहुल के समर्थन में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल, TMC सांसद शताब्दी रॉय और DMK सांसद डी एम कातिर आनंद ने बोलने से इनकार कर दिया।

“कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से 8 सांसदों को निलंबित करने, अमेरिका-भारत ट्रेड डील, एपस्टीन समेत अन्य मुद्दों पर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हाउडी मोदी-सरेंडर मोदी, नरेंद्र मोदी-सरेंडर मोदी, मोदी ट्रम्प-भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई और किसान विरोधी-नरेंद्र मोदी के नारे लगाए।”

राहुल गांधी

राहुल के समर्थन में 3 सांसदों का बोलने से इनकार

राहुल गांधी के समर्थन में विपक्ष के 3 सांसद नरेश उत्तम पटेल, शताब्दी राय, डीएम खातिर आनंद ने बोलने से इनकार दिया। राहुल आज भी हंगामे की वजह अपनी स्पीच पूरी नहीं कर पाए थे।

सम्पादकीय

यूजीसी नियमों पर 'सुप्रीम' रोक

पिछले दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने प्रमोशन आफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया। इन नियमों का मकसद शैक्षणिक संस्थानों से धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, नस्ल या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव को खत्म करना था, लेकिन इन नियमों ने व्यापक विवाद को जन्म दिया। सामान्य वर्ग के छात्र इस आशंका से घिर गए कि इन नियमों में उन्हें पहले से ही अपराधी मान लिया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इन नियमों में शिकायत की सत्यता जांचने या झूठी शिकायतों को छांटने का कोई ठोस प्रविधान नहीं दिखता। हर आरोप पर तुरंत समिति बैठाकर तेज कार्यवाही तो तय है, लेकिन साक्ष्य की परख, गवाहों की सुनवाई, गोपनीयता और अपील जैसी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। आरोप लगते ही कार्रवाई होने की जल्दी में सही जांच कैसे होगी? यह बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लक्ष्यों और संवैधानिक निष्पक्षता के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाएगी? वास्तव में न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि होते दिखना भी चाहिए, अन्यथा भरोसा टूट जाता है। कानूनी दृष्टिकोण से अनुच्छेद-14 के हिसाब से देखें तो यूजीसी के नए नियम समानता के अधिकारों की अनदेखी करते हैं, जबकि अनुच्छेद-15(1) जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने का प्रविधान करता है। अदालतों ने कई बार माना है कि गरिमा, निष्पक्षता और उचित प्रक्रियाओं तक पहुंच जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। यदि किसी शिक्षक या छात्र को जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वह अनुसूचित जाति या जनजाति या फिर ओबीसी में नहीं आता, तो उसके पास बचाव का कोई कानून न होना प्रक्रियात्मक अन्याय है। बड़ी बात यह है कि यूजीसी गाइडलाइन की धाराएं आपस में ही मेल नहीं खातीं। नियम-2 वंचित समूहों के खिलाफ भेदभाव मिटाने की बात करता है, दूसरी ओर नियम-3(सी) न्याय के अधिकार को केवल कुछ जातियों तक सीमित कर देता है। पिछले वर्ष फरवरी में यूजीसी ने नियमों का मसौदा संस्करण सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया था। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को जाति-आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया था। मसौदा नियमों में यह भी प्रस्ताव था कि भेदभाव की झूठी शिकायतों को 'हतोत्साहित' किया जाए और इसके लिए जुर्माने का प्रविधान रखा गया था, लेकिन अंतिम अधिसूचित नियमों में झूठी शिकायतों से संबंधित प्रविधान हटा दिया। वास्तव में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से निपटने वाले प्रविधानों को हटाना इस गाइडलाइन के लिए ढांचागत कमजोरी के रूप में सामने आया। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उच्च शिक्षा में 60 प्रतिशत विद्यार्थी आरक्षित वर्ग से थे। ऐसे में यह भी बड़ा सवाल है कि इन 60 प्रतिशत विद्यार्थियों में ही कोई किसी का जाति आधारित भेदभाव करता है तो क्या होगा? इस पर ये नियम चुप हैं। जिस प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और दहेज उत्पीड़न विरोधी धारा-498 ए के तहत कई बार ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां झूठे या गलत मामले दर्ज कराए गए और निर्दोष फंसे, वैसा ही खतरा यूजीसी के समता नियमों में भी दिख रहा था। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इनके दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए गिरफ्तारी से पहले प्राथमिक जांच सुझाए थे। दुनिया भर के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और शिक्षण प्रणालियां भी विविधता और समानता के सिद्धांत अपनाती हैं। अमेरिका के प्रत्येक विश्वविद्यालय के पास एक स्वतंत्र इकाई होती है, जो भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करती है। इस जांच प्रक्रिया में शिकायतकर्ता और आरोपी, दोनों के अधिकारों का ध्यान रखा जाता है। जांच प्रोटोकाल में साक्ष्यों के मानक, अपील का अवसर, गोपनीयता आदि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, ताकि न्याय हो भी और होता हुआ दिखे भी। अक्सर वहां बाहरी या तटस्थ जांचकर्ता नियुक्त किया जाता है, रिपोर्ट लिखित रूप में तैयार होती है और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। इसी तरह ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि की उच्च शिक्षण संस्थानों में भी एंटी-डिस्क्रिमिनेशन नीतियां सबके लिए समान होती हैं। कोई भी छात्र यदि उत्पीड़न झेलता है, चाहे वह अल्पसंख्यक समूह का हो या बहुसंख्यक का, उसके लिए शिकायत दर्ज करने और न्याय पाने का प्रविधान होता है। हार्वर्ड, आक्सफोर्ड आदि ने नियमित सेंसिटाइजेशन वर्कशाप, मेंटारिंग प्रोग्राम और डायवर्सिटी कोर्स-वर्क शुरू किए हैं, ताकि छात्र-छात्राओं में पारस्परिक सम्मान एवं संवेदनशीलता विकसित हो। समता का वास्तविक अर्थ है सभी के साथ न्याय। एक कमजोर को ताकत देकर दूसरे को कमजोर करना समाधान नहीं। सभी को साथ लेकर चलना ही टिकाऊ रास्ता है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहां कानून सबके लिए बराबर होता है। यही हमारे संविधान का मूलभाव है। अगर कहीं सामान्य वर्ग के छात्र के साथ गलत हो रहा है, तो उसे भी न्याय मिलना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाने पर भी काम हो, जहां शिकायत की नौबत कम आए।

मद्रास हाई कोर्ट ने दीपम पर डीएमके सरकार की नीति को राजनीति से प्रेरित बताया

> मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू अधिकारों को दबाने की राज्य सरकार की कोशिश को एक बड़ा झटका दिया है और एक मिसाल कायम की है। भले ही राज्य की मशीनरी बेशर्मी से हिंदू अधिकारों को दबाने और उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करने की कोशिश कर रही हो।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के उस आदेश को सही ठहराया जिसमें थिरुपरनकुंद्रम हिल पर दीपाथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार की कड़ी आलोचना की। साथ ही सरकार के कानून व्यवस्था की समस्या के दावों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के फैसले को बरकरार रखा जिसमें मशहूर थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर बने पुराने पत्थर के खंभे पर दीया जलाने का आदेश दिया गया था। यह भगवान मुरुगन के छह घरों में से एक माना जाता है। यह आदेश 6 जनवरी को जस्टिस जी. जयचंद्रन और जस्टिस के.के. रामकृष्णन की खंडपीठ ने दी थी। कोर्ट ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताई क्योंकि उसने साल में एक दिन होने वाले रस्म को करने की इजाज़त नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि इससे अशांति फैलेगी। बेंच ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को 'फिजुल और यकीन करने के लायक नहीं' बताया। मद्रास हाईकोर्ट ने सख्ती के साथ कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब ऐसी गड़बड़ी खुद राज्य द्वारा स्पॉन्सर की गई हो। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी राज्य अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए उस लेवल तक न गिरे। इससे सरकार को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जजों ने कहा कि अपील करने वालों जैसे- हज़रत सुल्तान सिकंदर बादुशा अवुलिया दरगाह और राज्य के अधिकारियों के पास सबूत नहीं हैं। इन लोगों के पास ऐसे सबूत नहीं हैं कि शैवों के 'आगम शास्त्र' में उस जगह पर दीया जलाने पर रोक है, जो सीधे गर्भगृह में भगवान की मूर्ति के ऊपर नहीं है। कोर्ट ने जोर देकर कहा, "निर्देश का मकसद सुरक्षा पक्का करना है। इसलिए जज द्वारा सुझाई गई दूरी की पाबंदी दीपम जलाने की जगह तय करने के लिए ज़रूरी शर्त नहीं है। दीपम जलाने की जगह तय करते समय सिर्फ धार की प्रॉपर्टी की सुरक्षा ही अहम है।" बेंच के अनुसार दीपम जलाने के लिए सबसे अच्छी जगह पत्थर का खंभा है, जो एक अलग चट्टान की चोटी पर है और उस चोटी के नीचे है जहाँ धार है। जजों ने धार्मिक कामों का मकसद भी बताया कि कार्तिकेयदीपम और दूसरे त्योहारों के दौरान अच्छी जगहों पर दीपम जलाने का रिवाज है, ताकि पहाड़ी और आस-पास के इलाकों में रहने वाले भक्त देख सकें और पूजा कर सकें। फिर उन्होंने संत थिरुमूलर का ज़िक्र किया, जिन्होंने कहा था कि 'रोशनी भगवान शिव का रूप है।' कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि देवस्थानम के पास अपने भक्तों की इच्छाओं को नज़रअंदाज़ करने का कोई कारण नहीं है। उसकी ज़मीन की सीमाओं के अंदर ऊँची जगहों पर दीये जलाने की परंपरा है। अदालत ने डीएमके सरकार से कहा कि कानून-व्यवस्था की आशंका 'एक काल्पनिक डर' है, जिसे राजनीतिक एजेंडे के लिए बनाया गया है। पीठ ने कहा, "यह मानना हास्यास्पद और मुश्किल है कि शक्तिशाली राज्य इस डर से दीपम जलाने की अनुमति नहीं दे रहा है कि इससे सार्वजनिक शांति भंग होगी"। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहाड़ी पर स्थित दीपस्तंभ की जगह श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की संपत्ति है। बेंच ने आरोप लगाया, "देवस्थानम से कुछ लोगों को दीया जलाने के लिए खंभे तक आने देना और भक्तों को पहाड़ी के नीचे ही रोककर पूजा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह दिखाना कि इस तरह के जमावड़े से शांति भंग होगी, भगदड़ मचेगी, समुदाय के बीच वैमनस्य बढ़ेगा, वगैरह, या तो यह दिखाता है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हैं या समुदायों के बीच सद्भाव लाने में हिचकिचा रहे हैं।" कोर्ट ने कहा कि राज्य को, जिला प्रशासन के जरिए इस मुद्दे पर हिन्दू मुस्लिम समुदायों के बीच भाईचारा और शांति लाने की कोशिश करनी चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि इतने सालों में शांति वार्ता ने सिर्फ शक बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि यकीन की कमी है। मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला किया कि थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर पुराना पत्थर का खंभा कार्तिगई दीपम का दीया जलाने के लिए सही है। हालांकि, खंभे के सिकंदर बादुशा दरगाह के पास होने की वजह से इसका विरोध हुआ और दीया आमतौर पर उचिपिलैयार मंदिर के पास एक अलग जगह पर जलाया जाता था । डीएमके ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए कोर्ट के आदेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं याचिकाकर्ता रामा रविकुमार ने ब्ॅथ् की मदद से पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन मदुरै डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने लोगों की सुरक्षा का हवाला देते हुए रोक लगा दी। इस स्थिति में मदुरै कमिश्नर जे लोगनाथन की अगुवाई में राज्य पुलिस ने श्रद्धालुओं को रोक दिया। हिंदू मुन्नानी के सदस्य समेत तमाम श्रद्धालुओं ने मंदिर के सामने जमा होकर कोर्ट द्वारा तय जगह पर दीया जलाने की इजाज़त देने की माँग की। मंदिर के मैनेजमेंट ने पिछले फैसले को यह कहते हुए चुनौती भी दी थी कि इस कार्रवाई से सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा हो सकता है। लेकिन, कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि शाम 6 बजे तक दीया जलाना होगा, नहीं तो शाम 6.05 बजे कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू होगी। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा, "मैंने खास तौर पर पुलिस को यह पक्का करने का आदेश दिया था कि भक्तों का पिटीशन में बताई गई जगह पर कार्यक्रम मनाने और पूजा करने का अधिकार बना रहे, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया।" फिर भी, तमिलनाडु सरकार और मदुरै के अधिकारियों ने बाद में फैसले को चुनौती देने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां भक्तों ने जस्टिस जी जयचंद्रन और केके रामकृष्णन की डिवीजन बेंच को बताया कि तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस एंड चौरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट कमिश्नर ने 17 दिसंबर को सनातन धर्म का 'खुलेआम अपमान और बेइज्जती' की है। हिंदुओं का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट एस श्रीराम ने कहा कि हर बार जब शांति बैठक में हिन्दुओं को अपने अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर गैर-कानूनी कब्जे के साथ-साथ वहां जानवरों की बलि देने, उसका नाम बदलकर सिकंदर हिल करने और एक इस्लामी त्यौहार पर उसे हरे रंग से रंगने की कोशिश की भी चर्चा की। यह भी बताया गया कि राज्य कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया, जिससे पता चले कि वह खंभा दीपाथॉन नहीं है। जानकारी के अनुसार इस मामले को लेकर विपक्षी नेताओं ने पार्लियामेंट से वॉकआउट भी किया था।

■ रामस्वरूप रावतसरे

विडंबना यह है ...

ललित गर्ग

नारी देह, नारी अधिकारः माहवारी पर सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि

भारत के सामाजिक विकास की यात्रा में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक निर्णायक कसौटी रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक आँकड़ों या बुनियादी ढाँचे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह अपने समाज के आधे हिस्से-महिलाओं को कितना सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देता है। इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त और सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मासिक धर्म स्वच्छता को गरिमा और स्वास्थ्य के साथ जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। स्कूलों में साफ-सुथरे शौचालय और पानी की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। इस निर्णय का उद्देश्य पीरियड्स के कारण लड़कियों की पढ़ाई में होने वाली बाधा को रोकना और उन्हें शर्मिंदगी से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं और विशेषकर स्कूली लड़कियों की माहवारी से जुड़ी समस्या पर दिया गया ऐतिहासिक निर्णय, एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिन का सवेतन पीरियड लीव नीति को भी मंजूरी दी है। यह फैसला स्कूलों में मासिक धर्म प्रबंधन की कमी

को दूर करने और छात्राओं के सम्मानजनक शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। स्कूलों में अनिवार्य रूप से सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने वाला संदेश है कि अब माहवारी जैसे विषय को चुप्पी, लज्जा और अज्ञान के अंधेरे में नहीं छोड़ा जा सकता। विडंबना यह है कि जिस माहवारी को प्रकृति ने जीवन-चक्र का अनिवार्य और स्वस्थ हिस्सा बनाया है, उसे हमारे समाज ने सदियों से अपवित्रता, अशुद्धता और वर्जना से जोड़ दिया। परिणामस्वरूप, करोड़ों महिलाएँ और किशोरियाँ न केवल शारीरिक कष्ट झेलती हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा, हीनभावना और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करती हैं। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में माहवारी के दौरान लड़कियों को रसोई, पूजा, स्कूल और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है। यह व्यवहार केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री की गरिमा और अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि "माहवारी स्वच्छता की कमी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाती है" इस पूरे विमर्श को एक नई संवैधानिक दृष्टि देती है। संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और गरिमा के अधिकार को यदि वास्तविक अर्थों में लागू करना है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्कूलों में सेनेटरी पैड की अनिवार्य व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अध्ययन बताते हैं कि स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लड़कियाँ किशोरावस्था में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। यह केवल शिक्षा का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज की बौद्धिक और नैतिक पूंजी की क्षति है। न्यायालय ने शिक्षा को एक 'मल्टीप्लायर राइट' बताया जो अन्य मानवाधिकारों के उपयोग की कुंजी है। न्यायालय ने इस निर्णय को केवल आदर्शों की घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश दिए। कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। इन पैड्स का एएसटीएम डी-6954 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य किया गया, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही, पैड्स की सहज, सुरक्षित और गोपनीय उपलब्धता के लिए स्कूलों में वेंडिंग मशीन या नामित अधिकारी की व्यवस्था तय की गई, जिससे छात्राओं की झिझक और असहजता पूरी तरह दूर की जा सके। इसके साथ ही स्कूलों में "मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन कॉर्नर" स्थापित करने का आदेश दिया गया, जहाँ अतिरिक्त यूनिफॉर्म, स्पेयर इनरवियर, डिस्पोजेबल बैग और आवश्यक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध होगी। दिव्यांग छात्राओं के लिए व्हीलचेयर-अनुकूल शौचालय और सहायक उपकरण जैसी विशेष सुविधाएँ अनिवार्य की गईं। निजी स्कूलों द्वारा निर्देशों की अवहेलना पर मान्यता रद्द करने का प्रावधान रखकर जवाबदेही को मजबूत किया गया, ताकि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि हर छात्रा के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके। माहवारी स्वच्छता केवल पैड उपलब्ध कराने तक सीमित विषय नहीं है। इसके साथ जुड़ा है स्वच्छ शौचालय, साफ पानी, कचरा निस्तारण की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्णकृसही जानकारी। आज भी अनेक लड़कियाँ पहली माहवारी के समय भय, भ्रम और अपराधबोध से घिर जाती हैं क्योंकि उन्हें पहले से कोई वैज्ञानिक और संवेदनशील जानकारी नहीं दी जाती। स्कूलों में यदि स्वास्थ्य शिक्षा को गंभीरता से लागू किया जाए और माहवारी को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाया जाए, तो यह डर और संकोच स्वतः समाप्त हो सकता है।

जहां तक इन ...

कमलेश पांडेय

भारत-अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक के सियासी व कूटनीतिक मायने

भारत की सियासत में भले ही हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के विपरीत ध्रुव समझे जाते हों लेकिन वैश्विक दुनियादारी में वे परस्पर पूरक बनते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि अरब जगत पर कसते अमेरिकी-चीनी शिकंजे के दृष्टिगत पश्चिम और मध्य एशियाई देशों की भलाई इसी में निहित है कि वे सभी 22 देश भारत-रूस और यूरोपीय देशों को साध कर चलें, ताकि कोई एक महाशक्ति या उनका दूसरा प्रतिद्वंद्वी देश मनमाफिक इनका दोहन-शोषण नहीं कर पाए। कूटनीतिक बिसात पर भारत का महत्व सभी देशों के लिए बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, चीन, रूस के समानांतर भारत एक मजबूत और अविवादित कूटनीतिक हस्ती के रूप में उभरा है, जिसकी सोच में वैश्विक प्रेम और पारस्परिक सद्भाव की भावना अंतर्निहित है। यही वजह है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में गत 31 जनवरी 2026 को लगभग एक दशक के अंतराल के बाद भारत-अरब लीग के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आयोजित हुई, जो भारत-अरब संबंधों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। खासकर जब ईरान पर अमेरिकी आक्रामक दवाब बढ़ रहा हो और इजरायल व अरब देशों में कूटनीतिक अविश्वास बढ़ता जा रहा हो, ऐसे में भारत और 22 अरब देशों के विदेश मंत्रियों या उनके समकक्षों की मुलाकात खास महत्व रखती है। वो भी तब जब भारत विरोधी पाकिस्तान, इस्लामिक नाटो बनाने पर आमादा दिख रहा हो और अरब के रक्तचूषकों के हाथ की कठपुतली बनता प्रतीत हो रहा हो। लिहाजा, लगभग एक दशक के अंतराल के बाद हुई इस दूसरी बैठक ने कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गहरे निहितार्थ बताए जाते हैं। जहां तक कूटनीतिक महत्व की बात है तो यह बैठक भारत और 22 अरब लीग सदस्य देशों के बीच सह-अध्यक्षता में संयुक्त अरब अमीरात

(यूएई) के साथ हुई, जिसमें अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति जैसे पांच प्रमुख क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने का रोडमैप तैयार किया गया। साथ ही अमेरिकी-इजयरली वर्चस्व वाले गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण, यमन-सूडान-लीबिया जैसे क्षेत्रीय संघर्षों और अमेरिका के 'बोर्ड ऑफ पीस' प्रस्ताव पर चर्चा से भारत ने मध्य-पूर्व में संतुलित मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अरब लीग महासचिव अहमद अबुल घीत और पीएम मोदी की मुलाकातों ने इसे और मजबूत बनाया। जहां तक इस बैठक के राजनीतिक निहितार्थ की बात है तो टैरिफ संकट और सऊदी-यूएई के यमन विवाद के बीच यह बैठक भारत को वैश्विक कूटनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित करती है, और भारत के धुर विरोधी समझे जाने वाले पाकिस्तान की मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिशों का कड़ा मुकाबला करती हुई प्रतीत होती है। वहीं, सीरिया जैसे देशों के मंत्रियों की संभावित भागीदारी से भारत ने एचटीएस (HTS) सरकार के बाद पहली मंत्री-स्तरीय बातचीत का रास्ता खोला। कुल मिलाकर, यह भारत की 'मल्टी-अलाइनमेंट' नीति को मजबूत करती है, जहां ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के साथ शांति पहल पर जोर दिया गया। उल्लेखनीय है कि भारत-अरब लीग के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2016 में बहरीन में आयोजित हुई थी।

जरा हटके

पिछले एक दशक ...

जयसिंह रावत

केंद्रीय बजट 2026-27: विकास की रफ्तार, उधारी की बैसाखी

भारत जैसे विकासशील देश के लिए केंद्रीय बजट महज़ आय और व्यय का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि वह सरकार की आर्थिक सोच, प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा का घोषणापत्र होता है। वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट भी इसी कसौटी पर खरा उतरता दिखता है। यह बजट एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करता है जो बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है, लेकिन इस विकास यात्रा का बड़ा हिस्सा उधारी की बैसाखी पर टिका हुआ है। यही वह बिंदु है जहाँ "विकास की अनिवार्यता" और "वित्तीय जोखिम" के बीच संतुलन साधना सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरता है। बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार केंद्र सरकार ने कुल 53.5 लाख करोड़ के व्यय का लक्ष्य रखा है, जबकि गैर-ऋण प्राप्तियां केवल 36.5 लाख करोड़ आंकी गई हैं। साफ है कि सरकार अपनी वास्तविक आय से लगभग 17 लाख करोड़ अधिक खर्च करने जा रही है। यही अंतर राजकोषीय घाटे के रूप में सामने आता है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.3 प्रतिशत है। तकनीकी रूप से यह पिछले वर्ष के 4.4 प्रतिशत से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन व्यवहार में यह संकेत देता है कि सरकार अब भी अपनी चादर से कुछ आगे पैर पसार रही है। इस पूरे परिदृश्य में एक सकारात्मक पहलू कर राजस्व का है। 28.7 लाख करोड़ की शुद्ध कर प्राप्तियां यह बताती हैं कि कर आधार में विस्तार हुआ है और औपचारिक अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) और प्रत्यक्ष कर संग्रह में निरंतर वृद्धि इस बात की पुष्टि करती है कि राजस्व जुटाने की क्षमता में सुधार हुआ है, हालांकि यह सुधार बढ़ते

खर्च के मुकाबले अभी भी अपर्याप्त नजर आता है। भारतीय आर्थिक विमर्श में अक्सर उद्धृत कहावत "ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत" आज के परिदृश्य में असहज रूप से प्रासंगिक लगती है। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार के कर्ज में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में जहाँ कुल केंद्रीय कर्ज लगभग 62 लाख करोड़ था, वहीं 2026-27 तक यह आंकड़ा 175 लाख करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। यानी एक दशक से थोड़े अधिक समय में कर्ज लगभग तीन गुना हो गया है। इस कर्ज का सबसे चिंताजनक पहलू ब्याज भुगतान है। आज बजट का एक बड़ा हिस्सा केवल पुराने कर्ज पर ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि सरकार का एक महत्वपूर्ण संसाधन न तो विकास कार्यों में लग पा रहा है और न ही सामाजिक क्षेत्रों में, बल्कि केवल अतीत की उधारी को संभालने में खप रहा है। यदि उधार लिया गया धन उपभोग या सब्सिडी तक सीमित रह जाए, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक जोखिम पैदा करता है। हालांकि इस तस्वीर का दूसरा, अपेक्षाकृत उजला पक्ष भी है। वर्ष 2026-27 के लिए 26.1 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया गया है। आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार यदि उधारी का पैसा सड़क, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्क और शहरी अवसंरचना जैसी स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में लगाया जाता है, तो यह केवल खर्च नहीं बल्कि भविष्य की उत्पादक क्षमता में निवेश होता है। संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल व्यय का लगभग आधा हिस्सा पूंजीगत कार्यों के लिए आवंटित किया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार उधारी को केवल उपभोग तक सीमित रखने के बजाय संपत्ति निर्माण की दिशा में ले जाना चाहती है। यदि ये परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं और उनकी गुणवत्ता बनी रहती है, तो वे आने वाले वर्षों में आर्थिक वृद्धि को सहारा दे सकती हैं। इसके बावजूद 17.2 लाख करोड़ की सकल बाजार उधारी चिंता पैदा करती है। जब सरकार बाजार से बड़े पैमाने पर कर्ज लेती है, तो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास निजी क्षेत्र को ऋण देने के लिए अपेक्षाकृत कम संसाधन बचते हैं। इससे ब्याज दरों पर दबाव बढ़ सकता है और निजी निवेश प्रभावित हो सकता है, जिसे अर्थशास्त्र में 'क्राउडिंग आउट प्रभाव' कहा जाता है। इसके साथ ही अनुमानित 55.6 प्रतिशत का ऋण-जीडीपी अनुपात भी एक चेतावनी संकेत है। यद्यपि यह कई विकसित देशों से कम है, लेकिन भारत जैसे उभरते बाजार के लिए यह स्तर सतर्कता की मांग करता है। वैश्विक रेटिंग एजेंसियां राजकोषीय अनुशासन और कर्ज प्रबंधन को गंभीरता से परखती हैं, और किसी भी तरह की चूक देश की साख पर असर डाल सकती है। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026-27 एक साहसिक लेकिन जोखिमों से भरा प्रयोग प्रतीत होता है। एक ओर पिछले दशक में तेजी से बढ़ा कर्ज है तो दूसरी ओर आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचे के निर्माण की तीव्र आकांक्षा। यदि यह पूंजीगत निवेश अगले कुछ वर्षों में आर्थिक वृद्धि दर को 7 से 8 प्रतिशत के आसपास बनाए रखने में सफल रहता है, तो कर्ज का बोझ संभालना अपेक्षाकृत आसान होगा लेकिन यदि वैश्विक मंदी, भू-राजनीतिक तनाव या घरेलू आर्थिक कमजोरियों के कारण विकास की रफ्तार थमती है, तो यही उधारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी बोझ बन सकती है। अंततः इस बजट की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार उपभोग आधारित खर्च को कितनी सख्ती से नियंत्रित कर पाती है और परिसंपत्ति निर्माण को कितनी ईमानदारी व दक्षता से आगे बढ़ाती है। विकास की दौड़ उधारी की बैसाखी पर नहीं बल्कि मजबूत आर्थिक अनुशासन के सहारे ही टिकाऊ बन सकती है।

टी-20 वर्ल्ड कप के वॉर्मअप मैचों का शेड्यूल जारी

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से खेलेगी, बीसीसीआई ने इंडिया ए की टीम भी जारी की

नई दिल्ली, एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से आगामी टी-20 वर्ल्ड कप से पहले खेले जाने वाले वॉर्मअप मैचों का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये अभ्यास मुकाबले 2 फरवरी से 6 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कुल 7 अलग-अलग मैदानों पर टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देंगी।इन वॉर्मअप मैचों का उद्देश्य टीमों को टूर्नामेंट से पहले पिच, मौसम और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का मौका देना है। खास बात यह है कि इस बार इंग्लैंड की टीम वॉर्मअप मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेगी, जबकि कई दिग्गज टीमें केवल एक-एक अभ्यास मैच ही खेलेंगी।ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमें भी वॉर्मअप चरण में सिर्फ एक-एक मुकाबला खेलेंगी। वहीं भारतीय टीम भी केवल एक वॉर्मअप मैच खेलेगी, जो 4 फरवरी को साउथ

भारतीय टीम का पहला मैच 7 फरवरी को USA से होगा।

अफ्रीका के खिलाफ मुंबई के डीवाई पाटील स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे खिलाड़ियों को टूर्नामेंट से पहले अपनी लय बनाने का मौका मिलेगा।भारतीय टीम के अलावा इंडिया ए की टीम भी दो वॉर्मअप मुकाबलों में हिस्सा लेगी। ये मैच युवा खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव हासिल करने का बड़ा अवसर होंगे। इंडिया ए की टीम का एक मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटील स्टेडियम में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका (USA) के खिलाफ खेला जाएगा। वॉर्मअप मैचों की शुरुआत 2 फरवरी को अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के बीच होने वाले

7 फरवरी से होगी वर्ल्ड कप की शुरुआत

टी-20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड और पाकिस्तान के मैच से होगी। जबकि भारत का पहला मैच अमेरिका के साथ मुंबई में खेला जाएगा। फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। इस मैच का वेन्यू पाकिस्तान के फाइनल पहुंचने या न पहुंचने पर तय होगा।

तिलक वर्मा को खेलना होगा एक वॉर्मअप मैच

BCCI ने वॉर्मअप मैच के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान भी कर दिया है। इसकी कप्तानी आयुष बडोनी करेंगे। तिलक वर्मा भी इस टीम का हिस्सा हैं। वे कम से कम एक मैच खेलकर अपनी फिटनेस साबित करेंगे। तिलक वर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान इंजर्ड हो गए थे। इंडिया ए टीमः आयुष बडोनी (कप्तान), नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, एन. जगदीशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, रियान पराग, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह, विपराज निगम, रवि बिश्नोई, खलील अहमद और मयंक यादव।

मुकाबले से होगी। यह मैच बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मैदान नंबर-1 पर खेला जाएगा।

सभी मुकाबलों के वीडियो हाइलाइट्स आईसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगे। भारत और साउथ अफ्रीका मैच की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर होगी। इसके अलावा, फैंस ये मुकाबले आईसीसी .टीवी पर मुफ्त लाइव देख सकेंगे।

टी-20 वर्ल्डकप का कैप्टन्स डे दो शहरों में होगा

मुंबई में 12 और कोलंबो में 8 टीमों के कप्तान शामिल होंगे

नई दिल्ली, एजेंसी

टी-20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है। इससे पहले, 5 फरवरी को ICC ने कैप्टन्स डे रखा। कैप्टन्स डे दो शहरों मुंबई (भारत) और कोलंबो (श्रीलंका) में होगा। कैप्टन्स डे एक मीडिया कार्यक्रम है, जहां कप्तान मीडिया से बात करेंगे। मुंबई में होने वाले कैप्टन्स डे मीट में कुल 12 टीमों के कप्तान हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम 5 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, कनाडा, इंग्लैंड, इटली, नामीबिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और वेस्टइंडीज के कप्तान शामिल होंगे। सभी कप्तानों को दो अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है, जो मीडिया से बातचीत के दौरान टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। ग्रुप-1 की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3:00 बजे और ग्रुप-2 की प्रेस

कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे शुरू होगी। यह कैप्टन्स डे मीट BCCI ऑफिस वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई) में आयोजित की जाएगी। 5 फरवरी को कोलंबो में भी कैप्टन्स डे का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नीदरलैंड, ओमान, पाकिस्तान, यूएई और जिम्बाब्वे की टीमों के कप्तान शामिल होंगे। यहां भी सभी कप्तानों को दो अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है, जो मीडिया से बातचीत करते हुए टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

फास्ट न्यूज

रोहित शेट्टी की 'गोलमाल 5' में अक्षय कुमार की एंट्री

नई दिल्ली। बॉलीवुड की चर्चित कॉमेडी फ्रैंचाइजी 'गोलमाल' अब अपनी पांचवीं कड़ी के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है और इस बार फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। खबर आ रही है कि अक्षय कुमार ने 'गोलमाल 5' में मुख्य विलेन के रूप में एंट्री की है, जो अजय देवगन और उनकी टीम के खिलाफ स्क्रीन पर दो-दो हाथ करेंगे। मुख्य कलाकारों में अजय देवगन फिर से इस फ्रैंचाइजी के मुख्य किरदार के रूप में नजर आएंगे।

छत पर पतंग उड़ाते नजर आए आमिर

अरिजीत सिंह से पश्चिम बंगाल मिलने पहुंचे एक्टर

मुबंई। अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया है। इसी बीच आमिर खान उनसे मिलने पहुंचे, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में से एक में आमिर खान पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। साथ ही लोग दोनों की मुलाकात की वजह भी जानना चाहते हैं। वीडियो में आमिर खान को पतंग उड़ाते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान एक्टर की टीम भी उनके साथ मौजूद नजर आ रही है। इसके अलावा दूसरे वीडियो में आमिर खान को कार से उतरते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान एक्टर पैपराजी का अभिवादन करते नजर आए। एक और वीडियो है, जिसमें वो अपनी कार में बैठे हैं और फोटोग्राफर्स उनकी एक झलक पाने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि आमिर खान सिंगर को मनाने आए हैं, ताकि वह अपना फैसला बदल दें। हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दोनों की मुलाकात की असल वजह क्या है। दरअसल, अरिजीत सिंह का घर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में है।

धुरंधर 2 का पोस्टर जारी

खून से सने खौफनाक लुक में दिखे रणवीर सिंह, बोले- अब बिगड़ने का वक्त आ गया

मुंबई। रणवीर सिंह की सुपरहिट फिल्म धुरंधर के दूसरे पार्ट का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने फिल्म धुरंधरः द रिवेंज का नया पोस्टर जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का टीजर आज दोपहर रिलीज किया जाएगा। जारी किए गए पोस्टर में रणवीर सिंह बेहद डरावने और इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। वह बारिश के बीच लाल रोशनी में खड़े दिख रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है मानो उन पर खून की बारिश हो रही हो। उनका चेहरा खून से सना हुआ है और आंखों में गुस्से और बदले की झलक साफ दिखाई दे रही है। यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे हिंदी के साथ-साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा, जिससे यह पैन इंडिया फिल्म बन जाएगी। आज रिलीज होने वाले टीजर को लेकर फैंस में काफी उत्साह है। माना जा रहा है कि धुरंधरः द रिवेंज साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित हो सकती है। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर. माधवन जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे। इसके अलावा सारा अर्जुन, राकेश बेदी और दानिश पंडोर ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं।

पहले पार्ट ने किया था 831.40 करोड़ का कलेक्शन

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। फिल्म ने भारत में कुल 831.40 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई थी। धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें देश की सुरक्षा और गुप्त मिशनों से जुड़ी कहानी दिखाई गई थी। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और सस्पेंस देखने को मिला था।

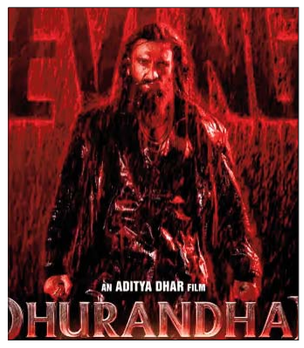

दमदार स्टारकास्ट ने बढ़ाया था फिल्म का आकर्षण

फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर. माधवन जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए थे। इसके अलावा सारा अर्जुन, राकेश बेदी और दानिश पंडोर ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं।

66 पोस्टर शेयर करते हुए रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, "अब बिगड़ने का वक्त आ गया है।" उनके इस कैप्शन ने फैंस की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। मेकर्स ने पोस्टर के साथ ही फिल्म के टाइटल का भी खुलासा कर दिया है। सीक्वल का नाम धुरंधरः द रिवेंज रखा गया है

अमेरिका-चीन के बीच फंसा भारत

नई दिल्ली। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पिछले महीने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के मंच से कहा था कि दुनिया की पुरानी व्यवस्था 'टूट' रही है। अब मध्यम ताकत वाले देशों को साथ लाकर काम करना होगा। दावोस में अपने भाषण में कार्नी ने न तो ट्रम्प प्रशासन का नाम लिया और न ही उन अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किया, जिनकी वजह से पुराना ग्लोबल सिस्टम हिल गया। अपने भाषण में उन्होंने सीधेतौर पर भले ही भारत का नाम न लिया हो, लेकिन इशारा साफतौर पर भारत की तरफ था। भारत इस वक्त दो बड़े दबावों के बीच खड़ा है। एक तरफ अमेरिका की बदलती नीतियां हैं तो दूसरी ओर चीन की बढ़ती आक्रामकता। ऐसे हालात में भारत अब पारंपरिक साझेदारों से आगे बढ़कर दुनिया के दूसरे हिस्सों में नए दोस्त तलाश रहा है।

डॉलर के मुकाबले रुपया 130 पैसे मजबूत, 90.20 पर आया

मुंबई। भारतीय रुपया मंगलवार (3 फरवरी) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 साल की सबसे बड़ी बढ़त के साथ 90.20 के स्तर पर पहुंच गया। यह तेजी अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के ऐलान के कारण हुई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय सामानों पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इससे पहले 2025 में रुपया करीब 5% तक टूटकर एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन गया था।

ईरान में प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ

गर्भाशय निकाले, सिर की खाल नोची गई, सबूत छिपाने के लिए शव जलाए

तेहरान, एजेंसी

ईरानी-जर्मन पत्रकार मिशेल अब्दोल्लाही ने ईरानी सरकार पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी सुरक्षा बलों ने विरोध करने वाली महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और म्यूटिलेशन (विकलांग करना) को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वह लोगों में ज्यादा से ज्यादा डर पैदा कर सके और संघर्ष रुक जाए। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, अब्दोल्लाही ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि उन्हें प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी मिली है। उनके अनुसार, गिरफ्तार महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, उनके गर्भाशय निकाल दिए जाते हैं, सिर की खाल उनके बालों सहित उतार दी जाती है और शरीर पर सिगरेट के जलने के निशान छोड़ दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के शव बहुत कम या बिल्कुल नहीं लौटाए जाते क्योंकि शासन उन्हें पहले जला देता है ताकि यातना के निशान छिप जाएं। अब्दोल्लाही ने आरोप लगाया कि

ईरान का इस्लामिक गणराज्य, खामेनेई के नेतृत्व में अपने लोगों के खिलाफ बलात्कार को हथियार बनाता है। यहां तक कि बच्चों के साथ भी ऐसी ही हिंसा की जा रही है। चाय, ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजें भी बहुत महंगी हो गईं। कई लोग पुरानी राजशाही (शाह का शासन) वापस लाने की मांग कर रहे थे। रॉयटर्स ने एक ईरानी अधिकारी के हवाले से 5,000 मौतें रिपोर्ट की। जबकि अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स इन ईरान ने 3,308 मौतों का अनुमान लगाया। दूसरे रिपोर्टों में मौतों की संख्या 2,000 से 6,000 तक बताई गई है। हालांकि ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया कि देशभर में कम से कम 12 हजार लोगों की मौत हुई है।

"प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ईरान में 8 जनवरी से इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय संचार बंद कर दिया गया था। मिलिशिया और यहां तक कि इराक से 5,000 शिया लड़ाकों को भी तैनात किया गया। सरकार और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स एजेंसियों ने मौत का आंकड़ा भी अलग-अलग बताया। ईरान की सरकारी एजेंसी ने 3,117 मौतें बताईं, जिनमें से ज्यादातर सुरक्षा बलों या निर्दोष लोगों की बताई गईं।

ईरान में महिलाओं ने हिजाब उतार विरोध जताया था

ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुई हिंसा 15 जनवरी तक चली थी। ये प्रदर्शन अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक माने जा रहे हैं। इनमें 5000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। यह हिंसा महंगाई के खिलाफ भड़की थी। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था।

विरोध प्रदर्शनों में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। शवगृह के बाहर अपने परिजनों के शव ढूंढते लोग।

गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को जबरन नग्न किया, इंजेक्शन दिए

जर्मन अखबार डाई वेल्ट ने भी प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से ऐसी ही घटनाओं की रिपोर्ट की है। एक गवाह ने बताया कि अधिकारियों ने घायल महिलाओं को कूड़े के ढेर की तरह गाड़ियों में लोड किया और कहा, हम तुम्हें अभी नहीं मारेंगे। पहले बलात्कार करेंगे, फिर मारेंगे। द गार्जियन अखबार ने भी केरमानशाह शहर में 16 साल की एक लड़की सहित कई प्रदर्शनकारियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना रिपोर्ट की, जहां सुरक्षा बलों ने डंडो से उनके शरीर को गलत तरीके से छुआ और बुरी तरह पीटा।

अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया

ट्रम्प बोले- रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से लेगा

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उसकी घोषणा कर दी। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रम्प ने अप्रैल में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ (जैसे को तैसा) लगाया था और रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% पेनल्टी का ऐलान किया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया था। अब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी तमसा संकेत को बताया कि भारत पर सिर्फ टैरिफ 18% ही लगेगा। अमेरिका रूसी तेल खरीदने के कारण लगा 25% टैरिफ हटा देगा। ट्रम्प ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ट्रेड डील की घोषणा की। ट्रम्प ने दावा किया

ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद से अब तक उनकी पीएम मोदी से फोन पर 7 बार बात हुई है।

कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं ट्रम्प के मुताबिक, जरूरत पड़ी तो भारत वेनेजुएला से तेल लेगा। भारत 'बाय अमेरिकन' नीति के तहत अमेरिका से 46 लाख करोड़ रुपए (500 अरब डॉलर) से अधिक का सामान खरीदेगा। वहीं, ट्रम्प के एलान के बाद पीएम ने X पर लिखा- भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रम्प का शुक्रिया।

तेजी: 2.53 लाख/किलो पर पहुंची ■ ₹4 लाख से गिरकर ₹2.4 लाख हो गई थी कीमत

तीन दिन की गिरावट के बाद चांदी ₹17 हजार बढ़ी

नई दिल्ली, एजेंसी

गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार तीन दिन की गिरावट के बाद आज तेजी 3 फरवरी को तेजी है। वायदा बाजार (MCX) में चांदी के दाम में करीब 17 हजार रुपए (7%) की बढ़त है। 1 किलो चांदी का भाव 2.53 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले तीन दिनों में चांदी की कीमत 1.60 लाख रुपए कम हो चुकी है। सोने में भी करीब 5 हजार रुपए (3%) की तेजी है। 10 ग्राम सोना 1.45 लाख रुपए पर आ गया है। बीते 3 कारोबार दिन में इसकी कीमत 26 हजार कम हुई थी। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है- AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी

कीमत कई सोर्सेज (जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट) से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सोने-चांदी की ट्रेडिंग होती हैं। शेयर बाजार की तरह हर सेकंड बोलियां लगती हैं जिससे दाम लगातार ऊपर नीचे होते हैं। यह वह जगह है जहां आप फिजिकल सोना-चांदी खरीदते हैं। फिजिकल गोल्ड को लाने, ले जाने और स्टोर करने का खर्च इसमें जुड़ा होता है।

सोने-चांदी में गिरावट की 2 वजह

■ **प्रॉफिट बुकिंग:** सोने-चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया।

■ **फिजिकल डिमांड में कमी:** ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएं भी बढ़ीं।

सर्राफा बाजार में चांदी ₹2.55 प्रति किलो बिक रही

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, आज सर्राफा बाजार में चांदी 2,55,372 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,50,708 रुपए है। बीते 3 दिनों मुनाफा वसूली के कारण सोने-चांदी की कीमत में गिरावट आई थी।

मार्जिन बढ़ने से सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव

सेबी रजिस्टर्ड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) ने कॉपर के बाद अब सोने और चांदी पर भी मार्जिन मनी बढ़ा दी है। सोने पर मार्जिन 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया है। वहीं चांदी पर इसे 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। मार्जिन बढ़ने से कीमतों पर दबाव बने रहने की उम्मीद है। कमोडिटी मार्केट में जब कोई बड़ा सौदा करता है, तो उसे पूरे पैसे तुरंत नहीं देने होते। उसे कुल कीमत का एक छोटा हिस्सा सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ता है, जिसे 'मार्जिन' कहते हैं। मार्जिन बढ़ने का मतलब है कि अब ट्रेडर्स को ज्यादा पैसा लगाना पड़ेंगे। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से खरीदारी की हुई है। मार्जिन बढ़ते ही एक्सचेंज उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। अगर उनके पास तुरंत पैसा नहीं है, तो उन्हें अपना सोना या चांदी बेचना पड़ता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ बेचते हैं, तो दाम गिरने लगते हैं।

नॉर्वे के डिप्लोमैट ने भारतीयों को सांप से बदतर बताया

एपस्टीन से कहा था- इंडियन और सांप मिलें, तो पहले इंडियन को मारो

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी करीब 30 लाख से ज्यादा फाइलें सार्वजनिक कर दी हैं। इन फाइलों के सामने आते ही कई बड़े और रसूखदार लोगों के छिपे हुए सच बाहर आ रहे हैं। इन्हीं दस्तावेजों में नार्वे के एक डिप्लोमैट टेर्जे रॉड-लार्सन का 25 दिसंबर 2015 का एक ईमेल है। इसमें उन्होंने भारतीयों को सांप से भी बदतर बताया है। दस्तावेजों से पता चला है कि एपस्टीन ने लार्सन को किसी भारतीय नेता का ईमेल फॉरवर्ड किया था। इसके जवाब में लार्सन ने कहा था कि 'जब आप एक भारतीय और एक सांप से मिलें, तो पहले भारतीय को मार डालो।' हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि लार्सन ने भारतीयों के खिलाफ ये मेल क्यों लिखा था। एपस्टीन फाइल से ये भी पता चला था कि लार्सन ने 2013 में

बिल गेट्स और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात की जानकारी सीधे जेफरी एपस्टीन को भेजी थी। यह मुलाकात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई थी। ईमेल में इस बैठक की पूरी रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया गया है कि बिल गेट्स ने पाकिस्तान में पोलियो खत्म करने के लिए की जा रही कोशिशों की तारीफ की थी और कहा था कि इस दिशा में पाकिस्तान ने अपने काम को दोगुना कर दिया है। वहीं, नवाज शरीफ ने साइंस और टेक्नीक को आगे बढ़ाने को लेकर अपनी सोच शेयर की थी। उन्होंने खास तौर पर युवाओं के लिए IT सेक्टर में नौकरियां पैदा करने, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट बढ़ाने, ई-गवर्नेंस और टेक पार्क बनाने की बात कही थी। लार्सन एक नॉर्वेजियन डिप्लोमैट रहे हैं। वे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष थे और UN में भी काम कर चुके हैं। साल 2020 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जब उनका नाम जेफ्री एपस्टीन से जुड़ा था। हाल ही में जब टेर्जे रोड-लार्सन से जब जेफ्री एपस्टीन से जुड़े मामलों पर सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पूरे मामले में वे लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। लार्सन नॉर्वे की लेबर पार्टी से जुड़े रहे हैं। साल 1996 में टैक्स से जुड़े मामले में गड़बड़ी की वजह से उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

पुलिस ने 2किमी खदेड़ा तो दूसरी जगह से पहुंचे आंदोलनकारी, खींचकर बस में भरा

यूजीसी के सपोर्ट में छात्रों का हंगामा

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में मंगलवार को बिरसा आंबेडकर फुले छात्र संगठन (बापसा) उत्तर प्रदेश के बैनर तले UGC गाइडलाइंस-2026 के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट पर एकत्रित हुए। गेट नंबर-3 से परिवर्तन चौक तक समर्थन मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक छात्रों को दौड़ाया। इस बीच दूसरी तरफ से छात्र परिवर्तन चौक पहुंच गए। वहां पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें टांग-टांगकर बस में बैठाकर ले गई। बापसा उपाध्यक्ष आकाश कठेरिया ने कहा- 2 दिन पहले यहां UGC के नए गाइडलाइंस के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। बाहरी गुंडे लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में आकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब धारा 144 नहीं लागू थी। अब धारा 144 लागू कर दी गई है। हम अपना प्रदर्शन करेंगे। कई जिलों से लोग आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यूजीसी के नए नियमों को पूरी तरीके से लागू किया जाए।

यूजीसी और सरकार से सीधी मांग

बिरसा आंबेडकर फुले छात्र संगठन का कहना है कि जब तक UGC गाइडलाइंस को पूरी तरह लागू नहीं किया जाएगा, तब तक उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय और बराबरी सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी। संगठन ने मांग की है कि आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और खाली पदों को तुरंत भरा जाए।

आरक्षण, प्रतिनिधित्व और नियुक्तियों पर सवाल उठाए

छात्र ने कहा- UGC गाइडलाइंस 2026 इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के साथ लगातार भेदभाव के आरोप सामने आ रहे हैं। संगठन ने OBC, SC और ST कोटे के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति में नॉट फॉउंड सूटेबल (NFS) जैसे प्रावधानों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

छात्रों ने कहा है कि देशभर में ओबीसी, एससी और एसटी के खिलाफ जातिवाद और भेदभाव के मामलों में लगभग 118 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और शीर्ष पदों पर आरक्षित वर्गों की भागीदारी को भी बेहद कम बताया गया है। इस दौरान छात्र ने पोस्टर लहराए। उसमें दावा किया- जनवरी 2020 तक किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी प्रोफेसर नियुक्त नहीं हुआ।

छात्रों का समर्थन मात्र परिवर्तन चौक तक पहुंच गया। वहां पर छात्रों ने बैठकर नारेबाजी की।

'यूजीसी के समर्थन में हम प्रदर्शन करेंगे'

बापसा उपाध्यक्ष आकाश कठेरिया ने कहा- 2 दिन पहले UGC के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। बाहरी गुंडे लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में आकर प्रदर्शन कर रहे थे, तब धारा 144 नहीं लागू थी।

गाय ने बच्ची को उठाकर पटका

अखिलेश बोले- जनता बुल-बुलडोजर का इलाज करेगी

- गाय बच्ची को खदेड़ते हुए आती है। उसके बाद सींग से मारकर जमीन पर पटल देती है।
- लोग बच्ची को गाय से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसको मारती रहती है।

तमसा संकेत,एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में एक गाय ने 12 साल की बच्ची को उठाकर पटक दिया। उसके बाद सींगों से मारा। बच्ची को बचाने आए लोगों को भी दौड़ाकर मारा। बच्ची काफी चोटिल हो गई है। उसका उपचार चल रहा है। अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले में फेसबुक पर पोस्ट करके भाजपा पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने लिखा है- आगामी चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज कर देगी। घटना चौक इलाके के चौपटिया का है। इसका CCTV फुटेज सामने आया है। उसमें दिख रहा है कि एक गाय बच्ची को अचानक मारने लगती है। बच्ची उससे बचकर भागने की कोशिश करती है। गाय बच्ची को दौड़ा लेती है। सींगों की मदद से पटक देती है। उसके बाद उसे मारती रहती है। गाय पर बच्ची को हमला करते देखकर आसपास 10-12 लोग पहुंच जाते हैं। वे सभी बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाय उसे नहीं छोड़ती है। जमीन पर गिरी बच्ची को सींगों से मारती रहती है। लोगों के काफी मशक्कत करने के बाद गाय बच्ची को कुछ सेकंड के लिए छोड़ती है। उसके बाद फिर से उसे मारने लगती है। इस दौरान बच्ची को बचाने आए लोगों पर भी हमला करती है। किसी तरह से लोग बच्ची को उससे बचाते हैं। बच्ची की पहचान चौपटिया निवासी 12 साल की रिद्धिमा उर्फ चिंकी के रूप में हुई। उसके पिता शैलेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि यहां छुट्टा जानवर घूमते रहते हैं। नगर निगम प्रशासन को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए बच्ची की नानी आशा रस्तोगी ने बताया कि 1 फरवरी को सुबह 11:30 बजे घटना हुई। गाय बेकाबू हो गई थी। बच्ची को बुरी तरह से मारा। उसके बच्ची के मुंह से खून निकल रहा था। उसका इलाज करा रहे हैं। हमको ये लग रहा है कि किसी तरह से हमारी बच्ची बच गई। स्थानीय निवासी मोहम्मद अमानतुल्लाह ने कहा यहां पर गोवंश और कुत्तों के चलते बहुत समस्या होती है। सड़क पर गोबर पड़ा रहता है। इसके कारण परेशानी होती है। मामले में उन्होंने कहा कि यह समस्या खत्म होनी चाहिए। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत की है। मामला सामने आने के बाद नगर निगम की टीम कार्रवाई करने के लिए चौपटिया पहुंची। पता चला कि इलाके में करीब सभी घरों में मवेशी पाले गए हैं।

फास्ट न्यूज

शब-ए-बारात पर ट्रैफिक डायवर्जन

लखनऊ। लखनऊ में मंगलवार-बुधवार (3-4 फरवरी) को शब-ए-बारात का त्योहार मुस्लिम समुदाय मनाएगा। इसके मद्देनजर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने एंबुलेंस, शव गाड़ी, फायर सर्विस और स्कूली गाड़ियों को चिकित्सकीय या अन्य आपात स्थिति में प्रतिबंधित मार्गों से भी निकाला जा सकेगा।

सिपाही की पत्नी ने खाया सल्फास

लखनऊ। लखनऊ के महानगर इलाके में सिपाही की पत्नी ने सल्फास की गोली खा ली। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से मैनपुरी निवासी विष्णु प्रेमी यादव 32वीं बटालियन सरोजनीनगर में आरक्षी के पद पर तैनात हैं। वह वर्तमान में महानगर स्थित 35वीं बटालियन के सरकारी आवास में पत्नी पंकज उर्फ रूबी यादव (35), बेटे विराट और बेटी गौरी के साथ रहते हैं। विष्णु प्रेमी यादव ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी पंकज उर्फ रूबी का बीते करीब 10 साल से मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा था। बीमारी के चलते वह डिप्रेशन में रहती थीं। परिवार जल्द ही सरोजनीनगर स्थित 32वीं बटालियन के सरकारी आवास में शिफ्ट होने वाला था।

लखनऊ पुलिस ने सपा पार्षद को घसीटते हुए गिरफ्तार किया

लखनऊ। लखनऊ में पुलिस ने करीब 100 मीटर तक घसीटकर सपा पार्षद को गिरफ्तार किया। उनके समर्थकों को दौड़ाकर पीटा। इससे गुस्साए बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों ने थाना घेर लिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देखकर मौके पर 5 थानों की पुलिस बुलाई गई। DCP और ACP मौके पर पहुंचे।

बीजेपी कार्यकर्ता बोले- माफी मांगे, विधायक राजेश्वर पर टिप्पणी की थी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंका-जूते मारे

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। सरोजनीनगर से भाजपा विधायक एवं पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा की गई टिप्पणी के बाद प्रदेश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अजय राय ने एक सार्वजनिक बयान में डॉ. राजेश्वर सिंह पर प्रदेश और देश को "लूटने" जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसे भाजपा नेताओं और समर्थकों ने पूरी तरह निराधार, आपत्तिजनक और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित करार दिया है। अजय राय ने अपने बयान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल डराने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने डॉ. राजेश्वर सिंह की पूर्व सेवाओं से जुड़ी एजेंसी को लेकर भी बिना किसी ठोस प्रमाण के आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को भाजपा ने न सिर्फ एक जनप्रतिनिधि की छवि धूमिल करने की कोशिश बताया है, बल्कि इसे संस्थाओं और प्रशासनिक सेवाओं का अपमान भी करार दिया है। भाजपा का आरोप है कि इसी ईमानदार छवि और जनसमर्थन से घबराकर कांग्रेस नेतृत्व तथ्यहीन आरोपों का सहारा ले रहा है। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि बिना किसी सबूत के इस तरह के बयान लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ हैं। प्रदर्शन के दौरान स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी अप्रिय घटना की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माहौल को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सरोजनी नगर की janta ने साफ कहा है कि डॉ. राजेश्वर सिंह के सम्मान और छवि से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जनता ने प्रदर्शन के माध्यम से यह बता दिया है कि यदि इस तरह की बयानबाजी जारी रही और माफी नहीं मांगी गई, तो इसका अभी और भी कड़ा विरोध किया जाएगा।

लखनऊ में समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, माफी की मांग

अजय राय के बयान के विरोध में डॉ. राजेश्वर सिंह के समर्थकों ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन शहीद पथ तिराहा, कानपुर रोड स्थित होटल हॉलिडे इन के सामने आयोजित किया गया, जहां सुबह 11 बजे से ही बड़ी संख्या में समर्थक जुटने लगे। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी टिप्पणी की कड़ी निंदा की और तत्काल सार्वजनिक माफी की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि एक जिम्मेदार राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा और आरोपों से बचना चाहिए।

"भाजपा नेताओं का कहना है कि डॉ. राजेश्वर सिंह देश के उन चुनिंदा अधिकारियों में रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे सेवाकाल में ईमानदारी, सख्ती और कानून के राज को प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में कई बड़े आर्थिक अपराधों, माफिया नेटवर्क और भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रभावी कार्रवाई हुई, जिससे अपराधियों और उनके राजनीतिक संरक्षकों में असहजता स्वाभाविक है।

रक्षा मंत्री और सीएम करेंगे ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण

22 फरवरी से खुलेगा दूसरा फेज, गोमतीनगर से डालीगंज तक 5-7 मिनट में सफर

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में गोमतीनगर के समतामूलक चौराहे से निशातगंज होते हुए हनुमान सेतु और आगे डालीगंज तक ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा फेज 22 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इसका लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कॉरिडोर खुलने के बाद डालीगंज से गोमतीनगर का सफर महज 5 से 7 मिनट में पूरा हो सकेगा। इससे रोजाना एक लाख से अधिक लोगों को जाम से राहत मिलेगी एलडीए की ग्रीन कॉरिडोर योजना के दूसरे फेज में समतामूलक चौराहे से निशातगंज तक का काम पूरा हो चुका है। निशातगंज चौराहे की रि-डिजाइनिंग भी लगभग पूरी है, सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। आगे बीरबल साहनी मार्ग से हनुमान सेतु तक सड़क चौड़ीकरण और डामरीकरण हो चुका है। यहां फ्लाईओवर का निर्माण भी पूरा हो गया है, जबकि चौराहे का काम अंतिम चरण में है। हनुमान सेतु से डालीगंज तक भी फ्लाईओवर बनकर तैयार है। चौराहे की रि-डिजाइनिंग का काम चल रहा है। अब पूरे रूट पर सिर्फ फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। समतामूलक से निशातगंज तक का हिस्सा करीब एक महीने से तैयार था, लेकिन लोकार्पण के इंतजार में बंद रखा गया। अब पूरे रूट को एक साथ खोले जाने की तैयारी है। आईआईएम से पक्का पुल तक ग्रीन कॉरिडोर के पहले फेज का काम पहले ही पूरा हो चुका है और करीब डेढ़ साल से वहां ट्रैफिक चल रहा है। हालांकि, इसका औपचारिक लोकार्पण नहीं हुआ था।

समतामूलक चौराहे से लेकर हनुमान सेतु मंदिर तक पुल भी तैयार हो गया है।

अमिताभ ठाकुर 6 फरवरी तक हो सकते हैं रिहा

वारंट बी निरस्त होने के बाद रास्ता साफ, देवरिया में जमा कराए जाएंगे बांड

तमसा संकेत, एजेंसी

देवरिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की रिहाई का रास्ता होता नजर आ रहा है। वाराणसी के बाद अब देवरिया में भी बांड जमा कराए जाएंगे। जमानतदारों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद वह जेल से बाहर आ सकेंगे। वारंट बी और कानूनी दांव-पेंच के चलते जमानत मिलने के 15 दिन बाद भी वह जेल से नहीं छूट सके थे अमिताभ ठाकुर को 9 जनवरी को वाराणसी कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद 19 जनवरी को देवरिया कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। उन्हें एक-एक लाख रुपए के दो बांड और दो जमानतदार पेश करने थे। इस बीच लखनऊ के तालकटोरा थाने में दर्ज एक अन्य मामले में वारंट बी जारी हो गया। जिसके चलते ये प्रक्रिया यहीं रुक गई। 30 जनवरी को लखनऊ CJM कोर्ट ने वारंट निरस्त करने का आदेश दे दिया। इसके बाद 2 फरवरी को वाराणसी कोर्ट में औपचारिकताएं पूरी हुईं। अब देवरिया कोर्ट में भी बांड भरकर जमानत की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण त्रिपाठी के अनुसार उनकी रिहाई 6 फरवरी तक हो सकती है। वारंट बी का जारी होनाअमिताभ ठाकुर की रिहाई की सबसे बड़ी अड़चन वारंट बी रहा। अमिताभ ठाकुर को सबसे पहले 9 जनवरी को वाराणसी कोर्ट से चौक थाने में कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले से जुड़े झूठे आरोप लगाने के मामले में जमानत मिली। इसके बाद 19 जनवरी को देवरिया जिला जज न्यायालय ने भी धोखाधड़ी के मामले में उन्हें जमानत दे दी।

8वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, आंते बाहर आईं

बरेली। बरेली में 8वीं के छात्र की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावरों के ताबड़तोड़ वार से उसके पेट से आतें तक बाहर आ गईं। छात्र ने दबंगों के गाली-गलौज करने का विरोध किया था। इसी बात पर झगड़ा हुआ। परिजन सूचना पर छात्र को हॉस्पिटल ले गए। जहां हालत में सुधार न होने पर उसे दिल्ली एम्स रेफर किया। लेकिन रास्ते में ही छात्र ने दम तोड़ दिया। घटना 30 जनवरी की है। छात्र की मौत 1 फरवरी को हुई। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने अब FIR दर्ज की है। हाफिजगंज के रिठौरा के मोहल्ला इंद्रपुरी वॉर्ड नंबर 4 में समीर अपने परिवार के साथ रहता था। पिता-माता और 5 भाई-बहन साथ रहते थे। समीर पांच भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था। उसका बड़ा भाई रिहान (23) और बड़ी बहन आलमीन (21) है। समीर से छोटे दो भाई और हैं, जिनमें फरमान (11) और अन्नू (8) हैं। समीर के पिता रिठौरा बाजार में कपड़ों का व्यापार करते हैं। समीर पढ़ाई के साथ-साथ दुकान के काम में भी पिता का हाथ बंटाता था। 30 जनवरी की शाम समीर (16) अपने दोस्त अर्श के साथ बाइक से घर का सामान लेने गया था। वह दूध लेकर वापस लौट रहा था।

घटना : 3 एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने के बाद भी बिगड़ी तबीयत, कुत्तों की तरह करने लगा था हरकतें

5 साल के बच्चे को कुत्ते ने काटा, मौत

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। आगरा में 5 साल के बच्चे की कुत्ते की काटने से मौत हो गई। कुत्ते ने घर के बाहर खेलते समय बच्चे के सिर और चेहरे पर काट लिया था। पिता ने कहा- उसे 3 रैबीज के इंजेक्शन लगवाए गए थे, फिर भी उसकी हालत बिगड़ती गई। वह कुत्तों की तरह हरकतें करने लगा। परिवार के लोग उसे आगरा और फिर दिल्ली ले गए। सफदरजंग अस्पताल से लौटने के बाद बच्चे की मौत हो गई। पूरा मामला पिनाहट थाना क्षेत्र के अतैयापुरा गांव की है। कुंवर सिंह अपने परिवार के साथ पिनाहट के अतैयापुरा गांव में रहते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी मनीषा और 3 बच्चे सुरभि (10), मोहित (8), छोटू (5) रहते थे। कुंवर सिंह ने बताया- 9 जनवरी को मैं गांव से बाहर कुछ काम से गया था। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे थे। उन्होंने बताया- घर के बाहर की शाम के समय मेरा सबसे छोटा बेटा छोटू खेल रहा था। अचानक एक पागल कुत्ता आया और उसने छोटू को काटने की कोशिश की। इससे वह डर कर गिर गया। वहां कुत्ते ने उसके सिर और चेहरे पर काट लिया। पत्नी और अन्य परिवार के लोग बच्चे को लेकर पिनाहट सीएचसी लेकर पहुंचे। पत्नी मनीषा ने कहा- वहां डॉक्टरों ने उसे नहीं देखा। पर्चा बनाकर भेज दिया। इसके बाद हम लोग उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। बाहर से इंजेक्शन खरीदकर लगवाया। हम लोग इसके बाद 27 जनवरी को बच्चे को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले गए। वहां भी डॉक्टरों ने मना कर दिया। आगरा के बाह तहसील के रुदमुली गांव के अरविंद भदौरिया के 8 साल के बेटे नैतिक को 2022 में कुत्ते ने काट लिया था। नौतिक बाह में अच्छेलाल पब्लिक स्कूल की चौथी क्लास में पढ़ता था। पड़ोसियों के मुताबिक, करीब डेढ़ महीने पहले स्कूल जाते हुए उसको कुत्ते ने काट लिया था। चोट ज्यादा नहीं आई थी।

पिता बोले- पहले इंजेक्शन के बाद दोबारा हम सीएचसी पहुंचे

पिता कुंवर सिंह ने बताया- 9 को एंटी रैबीज का इंजेक्शन लगवाने के बाद हम दोबारा सीएचसी पिनाहट गए। फिर 12 और 16 जनवरी को टीका लगवाया। तीसरा वैक्सीनेशन लगवाने के बाद बेटे को बुखार आ गया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह अजीब सी हरकतें करने लगा। फिर 17 जनवरी को हम उसे आगरा के एसएन मेडिकल कालेज में ले गए। दो दिन के इलाज के बाद भी कुछ फायदा नहीं। इसके बाद हम उसे घर ले आए। लेकिन बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो हम उसे 26 जनवरी को दोबारा आगरा ले गए। लेकिन इस बार डॉक्टरों ने जवाब दे दिया।

पिता कुंवर सिंह ने बताया- मैंने सुना किसी डॉक्टर ने कहा- इसे जहर का इंजेक्शन दे दो क्योंकि जहर ही जहर को काटेगा। फिर मैंने रात में ही बच्चे की छुट्टी कराकर घर ले आया। उसे आराम नहीं मिल रहा था। 1 फरवरी को छोटू की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मेरे बेटे की डॉक्टरों ने शुरुआत से ही इलाज में लापरवाही की थी।

पृष्ठ 01 का शेष...

यूपी में 32,679...

परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही जारी की जाएंगी। अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की अफवाह या गैर-आधिकारिक जानकारी से बचने की सलाह दी गई है। लिखित परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स ही फिजिकल टेस्ट में शामिल हो सकेंगे। फाइनल मेरिट में भी लिखित परीक्षा के नंबर जोड़े जाएंगे। हालांकि UPPRPB ने फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए लिखित परीक्षा पास करने के न्यूनतम पासिंग मार्क्स निर्धारित किए हैं। 31 दिसंबर की शाम योगी सरकार ने 32, 679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इनमें सिविल पुलिस के अलावा PAC, विशेष सुरक्षा बल यानी SSF, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर तक के पद शामिल थे। सिविल पुलिस में 10,469 पदों पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। जबकि PAC में पुरुषों के लिए 15,131 पद खाली हैं। UP SSF में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1341 वैकेंसी है।

अमेरिकी ट्रेड ...

मोदी ने लिखा- मुझे राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करके बहुत खुशी हुई। यह जानकर बेहद संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार फैसले के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रम्प का दिल से धन्यवाद। मोदी ने आगे लिखा- जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एकसाथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और आपसी सहयोग के नए और बड़े मौके खुलते हैं। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी पार्टनरशिप को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उत्सुक हूं। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने NDTV से बातचीत में भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा- कुछ तकनीकी कागजों पर अगले कुछ दिनों में दस्तखत होंगे, लेकिन डील लगभग तय है। गोर ने कहा- यह टैरिफ समझौता प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच कई सालों से चली आ रही मजबूत दोस्ती का नतीजा है। यह टैरिफ दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। पहले भारत पर काफी ज्यादा टैरिफ लगता था, लेकिन अब भारत उन देशों में आ गया है जिन पर कम टैरिफ है। राजदूत गोर के मुताबिक, ट्रम्प और मोदी की दोस्ती इस डील को पूरा करने में सबसे बड़ी वजह बनी। गोर ने कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इस व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के रिश्तों का अगला दौर शुरू होगा। इस बीच व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि अमेरिका, भारत से आने वाले सामान पर लगाया गया वह एक्स्ट्रा टैरिफ हटा देगा, जो रूस से तेल खरीदने के बदले सजा के तौर पर लगाया गया था।

युमनाम खेमचंद ....

इसके बाद 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद, 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 12 फरवरी 2026 राष्ट्रपति शासन खत्म होने की आखिरी तारीख है। मणिपुर में भाजपा सरकार का कार्यकाल 2027 तक है। इसलिए पार्टी की कोशिश है कि राष्ट्रपति शासन खत्म होने से पहले नई सरकार का गठन हो जाए। फिलहाल मणिपुर विधानसभा में BJP के 37 विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 32 सीटें मिली थीं, जबकि JD(U) के 5 विधायक बाद में BJP में शामिल हो गए। अन्य दलों में NPF के 5, कांग्रेस के 5, KPA के 2, JD(U) का 1 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। एक सीट मौजूदा विधायक के निधन के कारण खाली है।

ईसी ने 6 पत्रों ...

ऐसे में सवाल यह है कि असल में बदतमीजी कौन कर रहा है। ममता बनर्जी ने सोमवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ काली शॉल ओढ़कर दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी। उनके साथ SIR प्रभावित 13 परिवार और TMC के नेता भी थे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि ममता ने अपने मुद्दे CEC को बताए लेकिन उनका जवाब सुने बिना ही नाराज होकर चली गईं। मुलाकात के बाद ममता ने कहा, ₹मैं बहुत दुखी हूं। मैं दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हूं। मैंने आज तक ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा। वह इस तरह से बात करते हैं जैसे वह जमींदार हों और हम नौकर। चार राज्य बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव होने है। SIR तीन राज्यों में हो रहा है, लेकिन भाजपा-शासित असम में नहीं। क्योंकि वह 'डबल इंजन' राज्य है। पहले चरण में 58 लाख नाम हटाए गए हैं। पीड़ित लोगों को खुद का बचाव करने का कोई मौका नहीं दिया गया। हकीकत की जांच किए बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैंने चुनाव आयोग को छह पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हमारे लोग आयोग के प्रतिनिधिमंडल से मिले, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दिल्ली की प्रेस को शायद यह अंदाजा नहीं है कि बंगाल में क्या हो रहा है। इसमें आपकी गलती नहीं है, यह आज की व्यवस्था की गलती है, जहां असली मुद्दे सही तरीके से सामने नहीं आ पाते। मैं संसद की सदस्य नहीं हूं, इसलिए सीधे वहां नहीं बोल रही हैं, एक मोदी की दूसरे अमित शाह की। उन्होंने कहा- SC/ST एक्ट में संशोधन कराना ही उनकी मुख्य लड़ाई है। इसके लिए दिल्ली से बड़ा आंदोलन शुरू होगा। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा- देश इस समय बहुत अस्थिरता की स्थिति में गुजर रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो गणतंत्र का कॉन्सेप्ट होता है, जो सिद्धांत होता है, जो रिपब्लिक, वह बिल्कुल इस समय छिन्न-भिन्न हो चुका है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंध अच्छे नहीं हैं।

सस्पेंशन के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे अलंकार अग्निहोत्री

कहा- केंद्र सरकार में केवल दो लोगों की चलती

तमसा संकेत, एजेंसी

प्रयागराज। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन में हुए विवाद का मामला थम नहीं रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा देकर पूरे देश में चर्चा में आए बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री प्रयागराज पहुंचे हैं प्रयागराज में अलंकार अग्निहोत्री अपने निलंबन की कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इसी सिलसिले में वह प्रयागराज में अपने विधि सलाहकारों से मिलें। उनका कहना है कि वह निलंबन को चैलेंज करेंगे। बातचीत में उन्होंनें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपना नर्म रुख दिखाया, लेकिन केंद्र सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। अलंकार अग्निहोत्री नें कहा कि केंद्र सरकार एक कम्पनी की तरह चल रही हैं। इसमें सिर्फ दो लोगों की ही चलती

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676